जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 354 प्रभात अजमेर, शुक्रवार 25 जुलाई, 2025 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

कल तक 52 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने की बात थी

आज चुनाव आयोग ने यह आंकड़ा बढ़ाकर 68 लाख कर दिया है

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 24 जुलाई। इंडिया गठबंधन मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रोशित है, और ऐसे में बिहार का एस आई आर (स्पेशल इन्टैंसिव रिवीज़न) मुद्दा आने वाले दिनों में संसद में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है।

इंडिया गठबंधन चाहता है कि कांग्रेस केन्द्र सरकार पर दबाव डाले कि वह इस सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा कराए।

लेकिन सूत्रों का कहना है कि ग़ैर-सरकारी माध्यमों एवं चैनलों के ज़रिए सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि वह इस पर चर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार इस मामले में शामिल ही नहीं है। पूरा मामला चुनाव आयोग से जुड़ा है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, और सरकार इसके लिए न तो ज़िम्मेदार है और न ही जवाबदेह।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनावों का बहिष्कार करने का सुझाव दिया है, लेकिन इस पर अंतिम फ़ैसला इंडिया गठबंधन को सामूहिक रूप से लेना होगा और इसमें अभी समय लग सकता है, क्योंकि इस पर गंभीर चर्चा होना बाकी है।

- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में विजयी एनडीए व महागठबंधन में कुल सोलह लाख वोटों का अंतर था।
- विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता का कहना है, अगर विपक्ष ने यह मुद्दा पुरजोर ढंग से अभी नहीं उठाया तो चुनाव आयोग मतदाता सूची से नाम काटने का परीक्षण आसाम, पश्चिमी बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश में दोहरायेगा।
- अतः कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेताओं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आदि के दिलों को काफी उद्वेलित कर रहा है।
- सरकार की सोच है कि अगर विपक्ष को कुछ शिकायत व आशंका है तो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट/चुनाव आयोग के समक्ष जाना चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, किसी भी तरह से सरकार के अधीन काम नहीं करता। अतः सरकार किसी भी तरह चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

जो बात विपक्ष के लिए चिंता का विषय बन गई है, वह यह है कि कल चुनाव आयोग ने इससे प्रभावित मतदाताओं की संख्या 52 लाख बताई थी, लेकिन यह आज बढ़कर 68 लाख हो गई है। इस आंकड़े में वे लोग शामिल हैं, जो स्थानांतरित हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, जिनके नाम दो जगह हैं, आदि-आदि।

पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को मिले वोटों में मात्र 16 लाख का अंतर था, ऐसे में 68 लाख वोटरों को हटाए जाने की बात विपक्ष के लिए वास्तव में बेहद गंभीर और खतरनाक है।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर हम इस मुद्दे पर जोर नहीं देते हैं, तो मोदी और शाह की हिम्मत बढ़ेगी और वे अन्य राज्यों, जैसे असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, में यही रणनीति अपनाएंगे।

यही कारण है कि कांग्रेस के कई सहयोगी, जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीसलपुर बाँध का एक गेट खुला

टोंक, 24 जुलाई। राजस्थान में स्थित बीसलपुर डैम के कैचमेंट एरिया में भारी वर्षा के कारण पर्याप्त पानी भर गया है और अब यह डैम नीचे की ओर पानी छोड़ रहा है। पिछले 21 वर्षों में पहली बार जुलाई के महीने में डैम के गेट खोले गए हैं, क्योंकि जल स्तर बहुत अधिक हो गया है। पानी का स्तर 315.50 आर.एल. मीटर तक पहुँच गया, जिसके बाद जल निकासी के लिए गेट नंबर 10 को एक मीटर खोलकर 6000 क्यूसैक पानी की निकासी की गई

- आमजन से नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की गई है।

है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि बीसलपुर बांध पेयजल के लिए जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले के लोगों के लिए लाइफ लाइन है। बीसलपुर सहित, जिले के अन्य लघु, वृहद् एवं मध्यम बांधों में भी पानी की अच्छी आवक होने से लोगों को पेयजल एवं सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा तथा क्षेत्र में अच्छी फसल का उत्पादन होगा। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने आमजन से अपील की है कि नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं जाएं।

भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमैंट्स से 2030 तक व्यापार दोगुना होगा

इस एग्रीमैंट के तहत भारत का ब्रिटेन को निर्यात किया जाने वाला 99 प्रतिशत सामान ''ड्यूटी फ्री'' प्रवेश करेगा, जिससे टैक्सटाइल, जैम्स व ज्वैलरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स आदि सैक्टर को भारी बढ़ावा मिलेगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत के उदारीकरण के बाद के इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी व्यापार समझौतों में से एक पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमैंट (एफटीए), जो वर्षों से प्रक्रिया में था, में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, शुल्क बाधाओं को समाप्त करने और नई दिल्ली और लंदन के बीच आर्थिक संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

इसका आर्थिक प्रभाव चौंकाने वाला है। वर्तमान में लगभग 60 अरब डॉलर के आसपास रहने वाला द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। ब्रिटेन को इससे हर साल 25.5 अरब पाउण्ड का लाभ होने का अनुमान है, जबकि भारतीय निर्माता और सेवा प्रदाता प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

दोनों देशों के अधिकारियों द्वारा इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। यह समझौता केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह दो सबसे

- भारत में भी ब्रिटेन से आयातित जाने-माने सामान, स्कॉच व्हिस्की, जिन पर 150 प्रतिशत रेट से ड्यूटी लग रही थी, अब घटाकर 75 प्रतिशत कर देगा तथा अगले दशक तक यह ''इम्पोर्ट ड्यूटी'' 40 प्रतिशत हो जायेगी।
- इस प्रकार भारत द्वारा ब्रिटेन से आयातित लग्ज़री कारें, जैसे जैगुआर व लैण्डरोवर, पर इम्पोर्ट ड्यूटी 100 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी जायेगी।
- भारत के सर्विस सैक्टर को भी फ्री प्रवेश मिलेगा ब्रिटेन में। आईटी कंपनियों, फायनैंशियल सर्विसेज़, एजुकेशन, कंसल्टैंसी फर्म आदि को भी ब्रिटेन में काम करने की आज़ादी मिलेगी। अब तक भारतीय प्रोफेशनल्स के समक्ष ब्रिटेन के सोशल सिक्युरिटी पैमेंट की भारी समस्या थी। ब्रिटेन ने इन प्रोफेशनल्स को छूट देने की घोषणा भी की है, कि पहले तीन साल उन्हें सोशल सिक्युरिटी के लिये कुछ योगदान करने का बंधन नहीं रहेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'क्या मृत मतदाताओं को भी वोटर लिस्ट में बने रहने दिया जाए?'

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का विरोध कर रहे विपक्ष से जवाबी सवाल किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जुलाई। सर्वोच्च न्यायालय में 28 जुलाई को मामला पहुंचने से पहले ही, मुख्य चुनाव आयुक्त (सी.ई.सी.) ज्ञानेश कुमार ने आज अपने पक्ष में मजबूती से दलील दी और बिहार में होने वाले चुनाव से पहले मतदाता सूची की स्पैशल इन्टैंसिव रिविज़न (एस.आई.आर.) के कदम का जोरदार बचाव किया।

परेशान दिख रहे ज्ञानेश कुमार ने पूछा, ''क्या चुनाव आयोग मृत लोगों को मतदाता सूची में रहने दे?'' विदित है कि ज्ञानेश कुमार अपने कार्यकाल में अब तक विपक्ष के लगातार आरोपों और चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोपों से जूझते रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा करने के आयोग के कदम के पक्ष में तर्क दिए।

- इस केस पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता पुनरीक्षण का तगड़ा बचाव किया।
- विपक्ष के सवालों से घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्षी दलों पर कई सवाल दागे, कि क्या दोहरी वोटर आईडी वालों को वोटर लिस्ट में रखा जाना चाहिए, क्या विदेशी प्रवासियों को वोटर लिस्ट में रहने देना चाहिए?
- चुनाव आयोग द्वारा जारी डेटा के अनुसार, बिहार की वोटर लिस्ट से 56 लाख नाम हटाए जाएंगे, इनमें से 20 लाख मृत हैं, 28 लाख मतदाता अन्य राज्यों में हैं, 7 लाख का नाम एक से ज्यादा स्थानों पर रजिस्टर्ड हैं और एक लाख से मतदाताओं से सम्पर्क नहीं हो पाया है।

मुख्य चुनाव आयोग ने सवाल किया,

''जिन लोगों के पास डुप्लिकेट ई.पी.आई.सी. (इलैक्टर्स फोटो आइडैन्टिटी कार्ड) हैं, क्या उन्हें रहने देना चाहिए? क्या विदेशी नागरिकों को मतदाता सूची में होना चाहिए? फिर विरोध किस बात का है?''- उन्होंने जोर देकर कहा कि एक शुद्ध और पवित्र मतदाता सूची ही एक सफल लोकतंत्र की नींव होती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग का देह शोषण करने वाले अभियुक्तों को 20 साल की सजा

जयपुर, 24 जुलाई। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को डरा धमकाकर उसका कई बार देह शोषण करने वाले अभियुक्त शैतान और रविन्द्र को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने पीड़िता

- शोषण से पीड़ित युवती ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की थी।

के साथ कई बार दुष्कर्म कर नैतिक रूप से अकल्पनीय अपराध किया है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 31 मार्च, 2022 को पीड़िता के पिता ने जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी बेटी ने उसे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा से नाराज़ हिंदू वोटों पर नज़र है अखिलेश की

इस वोट बैंक को रिझाने के लिए अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जुलाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सैफई में एक शिव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं।

ऐसी चर्चाएं थीं कि सावन के पहले सोमवार को वे काशी विश्वनाथ मंदिर में यादव समुदाय के पारंपरिक जलाभिषेक कार्यक्रम में भाग लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय, उन्होंने सैफई में बन रहे मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

यह निश्चित रूप से एक चुनावी रणनीति है। 2027 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव भगवा खेमे और धर्मनिरपेक्ष खेमे, दोनों में चिंता और चर्चाओं का विषय बन गया है।

प्रश्न यह है कि क्या अखिलेश यादव के मंदिर दौरे, धार्मिक व्यवहार का सार्वजनिक प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग उन हिंदू मतदाताओं को आकर्षित कर पाएगा, जिनका भाजपा से मोह भंग हो गया है, तथा इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम-यादव वोटबैंक उनके साथ बना रहेगा।

2024 के लोकसभा चुनावों में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी) फॉर्मूले की सफलता ने अखिलेश यादव को यह विश्वास दिला दिया है कि वे अपनी राजनैतिक पहुंच को अपनी पारम्परिक सीमा से आगे ले जा सकते हैं।

'सॉफ्ट हिन्दुत्व' में उनके प्रवेश की कोशिश हाल ही में साफ तौर पर दिखाई दी है तथा सावन के पवित्र महीने में उनकी इन कोशिशों ने और गति पकड़ ली है। वे सावन के हर सोमवार (जो भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है), को शिव मंदिर से संबंधित वीडियो साझा कर रहे हैं।

ये वीडियो किसी अन्य मंदिर के नहीं, बल्कि उसी मंदिर के हैं, जिसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा इटावा जिले के लुहन्ना गांव में, उनके पैतृक स्थान सैफई के पास, बनवाया जा रहा है।

जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में यादव समुदाय के जलाभिषेक कार्यक्रम में उनकी गैरहाज़िरी के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, वहीं यह समझा जा रहा है कि वे भाजपा की हिंदुत्व शैली में ढलने की बजाय, अपनी एक अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाना चाहते हैं।

यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि काशी कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है और मंदिर के पुनरुद्धार को मोदी की धार्मिक विरासत

- सावन मास में हर सोमवार वे सैफई गाँव में स्वयं द्वारा बनवाए जा रहे शिव मंदिर का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, इस मंदिर का नाम उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के नाम पर केदारेश्वर धाम रखा गया है।
- मंदिर के नाम को लेकर भारी विवाद छिड़ गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने इसे सनातन धर्म के खिलाफ अखिलेश की साजिश बताया।
- अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो स्वयं को हिंदुत्व का सबसे ताकतवर ''आईकन'' मानते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भागवत ने 40 मौलानाओं के साथ मीटिंग की

नई दिल्ली, 24 जुलाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत की गुरुवार को हरियाणा भवन में 40 मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक हुई। बैठक ढ ाई घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी सहित कई मुस्लिम

- बैठक में जाने माने मुस्लिम धर्मगुरू शामिल हुए, उन्होंने कहा कि गत 100 साल में पहली बार इस तरह की मीटिंग हुई है।

धर्मगुरु शामिल हुए। यह बैठक संघ की दूसरे समुदायों के साथ मेल-मिलाप की कोशिशों की एक कड़ी थी।

आरएसएस प्रमुख के साथ हुई बैठक के बाद लखनऊ से आए टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैय्यद फ़ज़लुल्ल मन्नान रहमानी ने कहा कि बीते

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फ्री ट्रेड एग्रीमैंट के मार्फत ब्रिटेन ने भारत की समृद्धि व बढ़ते मार्केट पर पैसा लगाया है

इन्हीं दो कारणों से ट्रंप भी भारत पर भारी टैरिफ लगाने से हिचकिचा रहे हैं

-अंजन रॉय-
-अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-

वॉशिंगटन, 24 जुलाई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से कुछ साल पहले, प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने बड़े गर्व से लिखा था कि वह लंदन में अपने बिस्तर से उठे बिना दुनिया भर की सबसे बेहतरीन चीजें मंगवा सकते हैं, जिनमें भारतीय चाय भी शामिल थी।

समय के साथ दुनिया ने उल्टा रास्ता पकड़ लिया और यह लगभग असंभव हो गया कि लोग दुनिया भर के अच्छे सामान आसानी से मंगवा सकें, क्योंकि देशों के बीच टैरिफ (शुल्क) और व्यापारिक प्रतिबंध बहुत बढ़ गए थे। वैश्वीकरण के बावजूद ये शुल्क देशों के बीच माल की आवाजाही को धीमा करते रहे और इससे उपभोक्ताओं की संतुष्टि भी कम हुई।

अब लगता है कि यह स्थिति बदलने लगी है।

भारत और ब्रिटेन ने एक ऐसा समझौता किया है जिसे आमतौर पर ''फ्री ट्रेड एग्रीमैंट'' (एफटीए) कहा जाता है। आदर्श रूप में एक एफटीए तो बहुत ही सरल एक पंक्ति में लिखा जा सकता है, हम दोनों देशों के बीच माल और सेवाओं की आवाजाही पर सभी शुल्क हटाते हैं।

थोड़े तकनीकी भाषा में कहा जाए तो भारत को 99 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जो उसके अधिकांश निर्यात को कवर करती है। वहीं ब्रिटेन को 90 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्ति या कमी मिलेगी, जो उसके 85 प्रतिशत निर्यात को कवर करती है।

इसका मतलब है कि शुरुआत में ब्रिटिश कारें और व्हिस्की, भारतीय ग्राहकों के लिए सस्ती होंगी, वहीं ब्रिटिश उपभोक्ताओं को भारतीय वस्तुएं, जैसे सी फूड, प्रोसेस्ड फूड और दवाएं, कम कीमतों पर मिलेंगी।

असल में, एक व्यापार समझौता इससे कहीं अधिक जटिल होता है। मुक्त व्यापार समझौते में माल और सेवाओं के नियामित प्रवेश की व्यवस्था होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के लिए विस्तृत नियम और शर्तें होती हैं। व्यापार वार्ताकार अपने देश के हितों की रक्षा करते हुए अपने माल और सेवाओं को दूसरे देश में प्रवेश दिलाने के लिए कठिन मेहनत करते हैं।

दोनों पक्ष एक-दूसरे की व्यापार नीति को अच्छी तरह समझते हैं और केवल एक-दूसरे का सम्मान करते हुए ही एक प्रभावी और न्यायपूर्ण व्यापार समझौता किया जा सकता है। उम्मीद की जाती है कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता इस दिशा में अच्छी तरह से किया गया है, जैसा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर कई बार कह चुके हैं।

आम बात है, लेकिन अर्थशास्त्री हमेशा यह मानते आए हैं कि देशों के बीच व्यापार से सभी को फायदा होता है। व्यापार हमेशा एक देश की तुलनात्मक श्रेष्ठता के आधार पर होता है। यह माना जा सकता है कि कोई भी देश हर चीज में सबसे अच्छा नहीं हो सकता।

वह कुछ चीजों में अच्छा होता है और कुछ में नहीं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अक्सर ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच व्यापार का उदाहरण दिया है। जहां ब्रिटेन ऊनी कपड़ों में बेहतर था, वहीं पुर्तगाल उत्तम किस्म की वाइन बनाता था। इसलिए उन्होंने ऊनी कपड़े और वाइन का आपस में व्यापार किया। यही मॉडल कई अन्य देशों पर भी लागू होता है।

कम से कम इन दोनों देशों, भारत और ब्रिटेन, में अब जाकर एक व्यापार समझौता हुआ है जिससे ज्यादातर माल और सेवाओं की आवाजाही मुक्त हो सकेगी। ज्ञातव्य है कि भारत पूर्व में ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99 प्रतिशत व्यापार मूल्य अब शुल्क-मुक्त या फिर केवल 10 प्रतिशत के मामूली शुल्क के साथ होगा।

कई मामलों में जहां पहले भारी शुल्क लगता था, अब उसे बहुत कम कर दिया जाएगा जिससे यह दोनों देशों के उपभोक्ताओं के लिए किफायती बन जाए।

यह समझौता दोनों देशों को तुरंत कुछ खास उत्पादों में अधिक पहुंच देगा। उदाहरण के लिए ब्रिटिश कारें, खासतौर पर जैगुआर और लैंड

- ट्रंप को भी भय है कि अगर भारी टैरिफ लगाया भारत पर तो भारत का बढ़ता मार्केट कहीं और खिसक सकता है और अंततोगत्वा यह अमेरिका के हित में नहीं है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज निर्णय होगा उदयपुर फाइल्स रिलीज़ पर

नयी दिल्ली, 24 जुलाई। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली की हत्या पर बनी हिंदी फिल्म उदयपुर फाइल्स पर अंतरिम रोक जारी रहनी चाहिए या नहीं, उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर शुक्रवार को संक्षिप्त सुनवाई के बाद आदेश पारित करेगा।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने गुरुवार को संबंधित पक्षों की दलीलें विस्तार पूर्वक सुनने के बाद कहा कि कल इस मामले का निपटारा किया जायेगा।

फिल्म के निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया के फिल्म का प्रदर्शन शुरू होने में हो रही देरी के विरोध पर पीठ ने कहा, आपने सही इंतज़ार किया है, क्योंकि कानून यही चाहता है। मुद्दा यह है कि क्या

- उदयपुर फाइल्स पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)